

(ब) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी शर्तों क्या हैं, और उसके कार्यान्वयन के बारे में क्या कल्प विद्यार्थित है; और

(ग) भूतपूर्व शैक्तियों के कल्याण एवं उन्हें पुनः बसाये जाने के लिए क्या योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और तत्सम्बन्धी शर्तों क्या हैं ?

उप बसाने संबंधी तयार रखा शर्तों (बी) अधधीयन (एम) : (क) से (ग) रखा सेवाधों के कामिकों के बच्चों के लिए स्कूल बोलने की कोई विशेष योजना नहीं है। फिर भी, जिन स्थानों पर सेवा कामिक काफी बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां एक योजनाबद्ध तरीके से कामिकों के बच्चों के लिए प्राथमिक/पूर्व-प्राथमिक स्कूलों के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ है।

2. भूतपूर्व शैक्तिक के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:—

पुनर्वास :

- (1) सभी केन्द्रीय अंशात्मकों और विधानों में तीसरी श्रेणी (समूह 'ब') में 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी (समूह 'ब') में 20 प्रतिशत रिक्तियों का आरक्षण 30 जून, 1979 तक बढ़ा दिया गया है।
- (2) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीय-कृत बैंकों में तीसरी श्रेणी (समूह 'ग') में 17½ प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी (समूह 'ब') में 27½ प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था है।
- (3) राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर अलग-अलग प्रतिशत में आरक्षण की व्यवस्था है।
- (4) संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा आवेदन-पत्र शुल्क की प्रदायता से छूट दी गई है।
- (5) सेवा निवृत्ति से पहले तथा सेवा-निवृत्ति-बाद विभिन्न व्यवसायों और ट्रेडों में प्रशिक्षण देने/पाठ्यक्रम बनाने की व्यवस्था की गई है।
- (6) रोजगार तथा प्रशिक्षण महाविद्यालय में भूतपूर्व शैक्तिकों को रोजगार देने के लिए एक टीम का पठन किया गया है।

(7) भूतपूर्व शैक्तिकों को शीघ्र रोजगार विधानों के लिए कुछ राज्यों में विशेष क्षेत्र बोलने गए हैं।

- (8) अफसरों के लिए पुनर्स्थापना प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है ताकि वे सिविल में रोजगार पा सकें या अपना रोजगार शुरू कर सकें।
- (9) मकान, भूमि, ट्रेक्टर, व्यावसायिक गाड़ियाँ, याली टैक्सियाँ तथा रेडीमेटड कुर्कानें देना।
- (10) निकलाने कामिकों को 'जब बचाने संभल' तथा उरबन्ध ऐपेक्सियाँ देना।
- (11) लघु उद्योग तथा कृषि उद्योग बोलने में सहयोग देना।

कल्याण :

- (1) बिराए पर दिए गए मकान/भूमि को वापस करने में लेने के लिए अफसरों पर कानूनी सुरक्षा उठाया संहायता प्रदान करना।
- (2) मुफ्त कानूनी सहायता देना।
- (3) उनके बच्चों/आश्रितों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें देना।
- (4) बहिरी क्षेत्र में भूमि का प्रायटन/मकानों का आरक्षण, प्रादि।

Formulation of Plans for augmenting Source of Energy

1083. SHRI V. ARUNACHALAM: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have formulated plans for augmenting the source of energy from work animals in view of the country's dwindling fossil fuel reserves and the ever increasing oil prices; and

(b) if so, the particulars thereof?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) and (b). The Draft Five Year Plan 1978-83 lays priority for meeting the energy needs of the agricultural operations also through bullock power in the context of the small farms and the small farmer economy in the country and the availability of draught animals. Even though the policy for development of cattle would lay major emphasis on increasing the productivity of stock in respect of milk production, there would also be substantial improvement in the work capacity of male progeny. The plan envisages a comprehensive and planned crossbreeding of cattle with exotic dairy breeds. Such programme would help in a large measure in improving the draught capacity of the progeny from scrub animals that would be brought under the crossbreeding or selective breeding programme. Research and development activities to improve bullock-cart designs and socio-economic surveys to determine the precise role of bullock-carts have also been undertaken.

गिरिडीह में ताम्बा, टिन, स्टील का पता लगाना

1084. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने 1971-73 में अपने छिद्रण कार्य के दौरान बिहार के गिरिडीह जिले में गंगाबाद ब्लॉक में ताम्बा, टिन, सीसा, आदि का पता लगाना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन धातुओं की खुदाई और उत्पादन के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णा मुखर्जी): (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण ने 1971-73 के दौरान गिरिडीह जिला (बिहार) के गंगाबाद ब्लॉक में इन धातुओं के लिए कोई छिद्रण कार्य नहीं किया। लेकिन 1968-70 के दौरान इन क्षेत्रों में ताँबा, सीसा, जस्ता छिद्रण की गई थी, जिसका कोई उच्च-स्तरीय परीक्षण नहीं किया।

(ख) खान नहीं उठता।

4202 LS-5.

Scarcity of Kerosene and Cooking Gas

1085. SHRI SAUGATA ROY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether there is acute scarcity of kerosene and cooking gas in the major cities.

(b) the reasons for the scarcity; and

(c) the steps taken by Government to improve the distribution system?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). The sales of kerosene in the country as a whole during the period April to November, 1978, were about 2.586 million tonnes as against the allocation of about 2.560 million tonnes registering a growth of 12 per cent over the sales in the corresponding period last year. In spite of this, however, due to shortage of other alternative fuels like coal, soft coke and firewood, the demand for kerosene has gone up considerably. The spurt in demand has resulted in shortage of the product being felt in some locations in the country.

As regards liquefied petroleum gas (cooking gas), the demand of the existing customers is sought to be met in full. During the past few months, however, availability of liquefied petroleum gas was affected in some cities on account of labour problems, transportation bottlenecks, reduced availability from refineries due to planned or unscheduled shutdowns etc.

(c) In spite of shortfalls include oil availability from Iran and difficulties in obtaining crude oil and petroleum products from international market, all efforts are being made to ensure supplies of kerosene to various locations in the country according to the allocations. The State Governments have been also advised to keep a close watch over the distribution of kerosene for ensuring equitable distribution and preventing its going into the black market.